

न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़
पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 153/2023

जी.सी.एस.एस. नं. : 2023/232

1. राजस्थान स्टेट जरिये तहसीलदार अनूपगढ़

—प्रार्थी

बनाम

1. बृजलाल पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील व जिला अनूपगढ़...
.....(मृतक)
1/1. रूमा कान्त पत्नी बृजलाल जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील व जिला अनूपगढ़
1/2. प्रशान्त पुत्र बृजलाल जाति जाट निवासी नाहरावाली तहसील व जिला अनूपगढ़

—अप्रार्थी

रेफरेंस अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थिति :-

1. राजपैरोकार, प्रार्थी
2. श्री हरेन्द्र शेखों, अधिवक्ता अप्रार्थी

—:: निर्णय ::—

दिनांक :29.11.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि—

1. हस्तगत प्रकरण पूर्ववर्ती न्यायालय अति. जिला कलक्टर सूरतगढ़ (प्र.सं. 267/13) से क्षेत्राधिकारी परिवर्तन के कारण हस्तांतरित होकर प्राप्त हुआ है जिसका निस्तारण किया जा रहा है। तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा राजस्थान स्टेट की ओर से अप्रार्थी बृजलाल के विरुद्ध यह रेफरेंस प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि तहसील अनूपगढ़ के ग्राम नारावाली में खसरा सं. 133 में कुल 66.16 बीघा भूमि जोहड़ दर्ज थी। उपनिवेशन विभाग की चकबन्दी के दौरान उक्त रकबा चक 2 एनएम के प.नं. 22/47 कि.नं. 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25 कुल 20 बीघा रकबा सीमांकित किया गया। उक्त वर्णित 20 बीघा भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जोहड़ के लिए आरक्षित थी। तथा वर्षा के जल के भराव तथा उपयोग में आने के लिए आरक्षित की गयी थी। उक्त भूमि का किसी अन्य कार्य के लिए आरक्षण, आवंटन तथा उपयोग गैर कानूनी हैं। राज. टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार उक्त भूमि किसी व्यक्ति को आवंटित नहीं की जा सकती तथा ऐसी भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते।

इस संबंध में राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा सिविल याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम स्टेट में दिनांक 02.08.2004 को निर्णय पारित किया गया है। साथ ही याचिका सं. 11153/2011 सुओमोटो बनाम सरकार में पारित आदेश दिनांक 29.05.2012 में जोहड़ नाला, तालाब नदी के कैचमेन्ट ऐरिया की भूमि के आवंटन को अवैध माना है। उक्त निर्णय द्वारा ऐसे आवंटनों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी सिविल अपील सं. 1132/11 जगपाल सिंह बनाम पंजाब राज्य में दिनांक 28.01.2011 को इसी प्रकार का आदेश पारित किया गया है। राजस्थान सरकार के द्वारा परिपत्र सं. प.10(3) राज-6/2001 पार्ट/5 दिनांक 26.06.2012 एवं परिपत्र सं. प.3(146)राज-7/2011 दिनांक 26.06.2012 जारी किये गये हैं।

उक्त भूमि जोहड़ की होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16(2) व 16(6) के अनुसार उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नहीं होते हैं। भूमि का आवंटन गैर कानूनी होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जोहड़ हेतु आरक्षित उक्त भूमि में से वर्तमान जमाबंदी अनुसार चक 2 एनएम के प.नं. 22/47 मु.नं 14 कि.नं. 2 ता 9/2.024, 12 ता 19/2.024, 22/0.228, 23/0.228, 24/0.228, 25/0.227 कुल 4.959 है। भूमि अप्रार्थी के दादा को आवंटित हुई थी जो वर्तमान रिकार्ड में अप्रार्थी के नाम खातेदारी दर्ज है। अप्रार्थी को किया गया आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। आवंटन निरस्त कर भूमि गै.मु. जोहड़ दर्ज



जिला कलक्टर
अनूपगढ़

किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किये जाने हेतु निवेदन किया।

2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी बृजलाल जरिए अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी को आवंटित नहीं हुई बल्कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि रियासतकाल से अप्रार्थी के पूर्वजों को मलकीयती थी व अप्रार्थी के पूर्वज भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे। प्रार्थी ने भूमि आवंटन होने का कोई सबूत पेश नहीं किया है। भूमि अप्रार्थी को आवंटित नहीं हुई बल्कि काश्तकारी अधिनियम 1955 लागू होने के पूर्व से ही अप्रार्थी के पूर्वजों की मलकीयती रही है। कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई जोहड़ पायतन नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई जोहड़ पायतन ही है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी कृषि भूमि के जोहड़ पायतन होने का अन्तिम सबूत नहीं है। वर्तमान में जोहड़ पायतन हेतु कोई आवश्यकता नहीं है। पेयजल हेतु डिग्गीयां बनी हुई है। प्रार्थना पत्र खारिज करने हेतु निवेदन किया।
3. अप्रार्थी की मृत्यु हो जाने के कारण अप्रार्थी बृजलाल के वारिसान को रिकार्ड पर प्रतिस्थापित किया गया। राजपैरोकार एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने निवेदन किया कि प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से लिखित बहस पेश की गयी है। राजपैरोकार प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी के नाम से रिकार्ड में दर्ज खातेदारी भूमि जोहड़ की थी, जो आवंटित नहीं की जा सकती थी। आवंटन विधिविरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य हैं। इसलिए आवंटन निरस्त करने तथा भूमि को रिकार्ड में गै.मु. जोहड़ दर्ज किये जाने के आदेश के लिए माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को रेफरेंस करने के लिए निवेदन किया। वकील अप्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि अप्रार्थी को आवंटित नहीं हुई बल्कि उक्त कृषि भूमि अप्रार्थी को विरासत में प्राप्त हुई है। वादग्रस्त भूमि रियासतकाल से अप्रार्थी के पूर्वजों को मलकीयती थी व अप्रार्थी के पूर्वज भूमि को काश्त करते चले आ रहे थे, कृषि भूमि में किसी प्रकार का कोई जोहड़ पायतन नहीं रहा और ना ही वर्तमान में कोई जोहड़ पायतन है, न ही जोहड़ की आवश्यकता है। उक्त भूमि अप्रार्थी के पूर्वजों को तबादला में प्राप्त हुई है। क्षेत्र में राजस्थान नहर योजना आने के बाद मुरब्बा बंदी के दौरान प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी के पूर्वज पानाराम को तबादला में राजस्थान सरकार द्वारा राजकीय भूमि दी गयी। उक्त भूमि जोहड़ पायतन नहीं थी। भूमि पर कभी जोहड़ नहीं रहा ना ही कभी वर्षा आदि का बहाव क्षेत्र रहा। वर्तमान में ईलाका नहरी है। पेयजल हेतु डिग्गीयां व वाटर वर्क्स बने हुये है कथित जोहड़ की भूमि में चारों तरफ काश्तशुदा खातेदारी भूमि है जिसमें काश्त की जाती है। इस स्थान पर वर्षा का जल आने के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस भूमि में जोहड़ बनाना सम्भव नहीं है इस भूमि को जोहड़ के लिए आरक्षित करना अव्यवहारिक होगा। अप्रार्थी अपनी आजीविका हेतु कृषि भूमि पर निर्भर हूं। भूमि अप्रार्थी को अपने दादा पानाराम से वसीयत के जरिये प्राप्त हुई। अगर यह भूमि अप्रार्थी से वापिस ली जाती है तो मेरे पास अपनी आजीविका को कोई जरिया नहीं बचेगा। प्रार्थना पत्र अस्वीकार करने हेतु निवेदन किया।
4. बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 में प्रावधान हैं कि -

Power to call for records and proceedings and reference to State Government of Board - The Settlement Commissioner or the Director of Land Records or a Collector may call for and examine the record of any case decided or proceedings held by any revenue court or officer subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of the order passed and as to the regularity of proceedings;

and, if he is of opinion that the proceedings taken or order passed by such subordinate court or officer should be varied cancelled or reversed, he shall refer the case with his opinion thereon for the orders of the Board, if the case is of a judicial nature or connected with settlement, or for the orders of the State Government if the case is of a non-judicial nature not connected with Settlement;

and the Board or the State Government, as the case may be, shall thereupon pass such order as it thinks fit.



जिला कलेक्टर
अपूर्णा

धारा 82 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के उपबंधों के अनुसार जिला कलक्टर को अपनी राय के साथ प्रकरण राजस्व मण्डल को प्रेषित किया जाना होता है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधि अनुरूप हैं।

5. प्रकरण में अप्रार्थी के द्वारा प्रश्नगत भूमि तबादला में प्रदान किये जाने का कथन किया गया है और यह भी कथन किया गया है कि उक्त भूमि जोहड़ व पायतन की नहीं थी परन्तु प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों रिपोर्ट पटवारी एवं दस्तावेज जमाबंदी, सूची सं. 4 आदि के अनुसार भूमि जोहड़ पायतन दर्ज थी। जो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि होने के कारण आवंटन नहीं की जा सकती थी। अप्रार्थी के द्वारा अपने जवाब पत्र में अंकित किया गया है कि उक्त भूमि कभी जोहड़ के रूप में उपयोग में नहीं ली गयी परन्तु इस संबंध में उनके द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मा. सर्वोच्च न्यायालय एवं मा. उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की अनुपालना में प्रश्नगत भूमि पूर्व में राजस्व रिकार्ड में जोहड़ पायतन दर्ज थी जिसका किसी को आवंटन किया है तो वो अवैध है। अतः अप्रार्थी के पक्ष में रिकार्ड में दर्ज भूमि का पारित आवंटन आदेश अवैध होने के कारण आवंटन खारिज योग्य होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए प्रकरण निर्णय हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को रेफरेंस किया जाना उचित है।
6. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से रेफरेंस किये जाने की हद तक स्वीकार करते हुए आगामी कार्यवाही के लिए अप्रार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत रेफरेंस किये जाने हेतु पत्रावली मय आदेश माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को प्रेषित की जावे। प्रार्थी तहसीलदार अनूपगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि मूल पत्रावली न्यायालय से प्राप्त कर निर्धारित समयावधि में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। तहसीलदार अनूपगढ़ के नाम से आदेश की पृथक से तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 29.11.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(अवधेश मीना)
 जिला कलक्टर A.S.
 कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
 अनूपगढ़